मासिक हिन्दी

विश्वनाथ समाचार

RNI No. MPHIN/25/A4357

'जनता की सोच — जनहित की खोज'

vishwanathsamachar@gmail.com

वर्ष 1 अंक 7 | इंदौर, सोमवार (15 जून 2026 से 14 जुलाई 2026 तक) | पृष्ठ 8, मूल्य 5 रुपया

अनमोल वचन

'सफलता का रहस्य यह है कि अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और पूरे मन, वचन तथा कर्म से उसे प्राप्त करने में जुट जाओ। '

- स्वामी विवेकानंद जी

एमपी- मुरैना में ट्रेन से कटकर 4 यात्रियों की मौत

इनमें 3 महिलाएं, एक बच्चा; आग की अफवाह से उतरे,दूसरी ट्रेन की चपेट में आए

मुरैना। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ट्रेन से कटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मोबाइल ब्लास्ट से आग लगने की अफवाह के बाद उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से कुछ यात्री घबराकर कर नीचे उतर गए। इनमें चार यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। मरने वालों में 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। जानकारी के मुताबिक, हादसा उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के हेतमपुर-धौलपुर रेलखंड पर हुआ। गाड़ी संख्या 19665 खजुराहो-उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस रविवार करीब 4:15 बजे हेतमपुर और धौलपुर स्टेशन के बीच अचानक रुक गई थी।

रेलवे के अनुसार, कोच में अलार्म चेन पुलिंग की गई थी, जिसके कारण ट्रेन बीच सेक्शन में रुक गई। इसी दौरान ट्रेन के एक कोच में मोबाइल ब्लास्ट जैसी अफवाह फैल गई, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। कई यात्रियों ने जल्दबाजी में ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से उतरे कुछ यात्री पास की अप लाइन पर पहुंच गए। इसी दौरान गाड़ी संख्या 20424 फिरोजपुर-सिवनी पातालकोट एक्सप्रेस वहां से तेज रफ्तार में गुजर रही थी। ट्रैक पर मौजूद 4 यात्री उसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। बागेश्वर धाम से लौट रही यात्री पूजा के अनुसार, कोच में मोबाइल ब्लास्ट की अफवाह फैलते ही अफरा-तफरी मच गई। चेन पुलिंग के बाद ट्रेन रुकते ही यात्री घबराकर नीचे उतर गए और ट्रैक की ओर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचीं। घायलों की तलाश और राहत कार्य शुरू किया गया। रेलवे ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और प्रारंभिक कारणों की पुष्टि की जा रही है।

राज्य सरकार प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना को कर रही है प्रोत्साहित : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ एमएसएमई की जाएंगी स्थापित

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। छोटे उद्योग करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश में रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। हमारा उद्देश्य वर्ष 2047 तक प्रदेश में एक करोड़ एमएसएमई स्थापित करने का है। सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यम प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हर जिले में उद्योग, हर परिवार में रोजगार और हर युवा को अवसर देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। जिस प्रकार हर 12 वर्ष में सिंहस्थ स्नान का अवसर मिलता है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के सुशासन के 12 वर्ष से देशवासियों को अमृत स्नान का अवसर प्राप्त हुआ है। बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में एमएसएमई क्षेत्र का कायाकल्प हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में एमएसएमई उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स तथा अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से प्रोत्साहन राशि और हितलाभ वितरण के लिए आयोजित 'समृद्ध एमएसएमई- विकसित मध्यप्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुआ। इस अवसर पर प्रदेश में एमएसएमई, स्टार्ट-अप प्रोत्साहन के लिए संचालित गतिविधियों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंगल क्लिक से 900 एमएसएमई यूनिट्स को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 6 ईटीपी निर्मित करने वाली इकाइयों को दो करोड़ 02 लाख की रुपये सहायता, विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को एक करोड़ 07 लाख रुपये मण्डीशुल्क की प्रतिपूर्ति और 11 इकाईयों का विद्युत टैरिफ रुपए तीन करोड़ 69 लाख रुपये का वितरण सिंगल क्लिक से किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण राशि, भू-आवंटन पत्रक तथा स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया। विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव का अभिनंदन किया। इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश मिश्रा, अलाना ग्रुप के संस्थापक सुश्री राशि बहल मेहरा और उद्यमी श्री कुणाल ज्ञानी ने मध्यप्रदेश में उद्यम स्थापित करने के संबंध में अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डिक्की के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अनिल सरवैया तथा उद्यमी श्रीमती प्रतिभा यादव, डॉ. सुरेश दुबे, श्री दिनेश चंदवानी, श्री यशराज वर्मा से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्यमशीलता और नवाचारों में मध्यप्रदेश, देश में अग्रणी है। प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में सवा करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसमें 4 लाख 41 हजार से अधिक इकाइयों की कमान बहनें संभाल रही हैं, यह महिला सशक्तिकरण का उदाहरण भी है। आगामी ढाई वर्षों में 4 हजार 500 करोड़ रुपये देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को मजबूती देने का लक्ष्य है। एमएसएमई विकास, नीति उद्यमियों को मजबूती प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत निवेश पर 40 प्रतिशत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 60 प्रतिशत तक प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को 8 प्रतिशत अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है।

एमएसएमई क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर भूमि उपलब्ध कराने के लिए नियमों को सरल किया गया है। पिछले ढाई वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र और 14 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही 1 हजार 63 भूखंड, उद्यमियों को आवंटित किए जा चुके है। आने वाले ढाई वर्षों में 60 नए औद्योगिक क्षेत्र और क्लस्टर विकसित करने और 6 हजार से अधिक भू-खंड नए उद्यमियों को देने का लक्ष्य है।

79 करोड़ की सड़क बनी 'ब्लैक स्पॉट कॉरिडोर': 8 साल में धंसी सड़क, बढ़े हादसे; ग्रामीण बोले- जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। देपालपुर से बनेडिया-अटाहेड़ा तक लगभग 35 किलोमीटर लंबी सड़क आज भ्रष्टाचार, निर्माण गुणवत्ता पर सवालों और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक बन गई है। करीब आठ वर्ष पूर्व 79 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह महत्वपूर्ण मार्ग अब लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि जोखिम का कारण बन गया है। सड़क की हालत इतनी जर्जर हो चुकी है कि क्षेत्र के ग्रामीण इसे अब 'ब्लैक स्पॉट कॉरिडोर' और 'डिलीवरी रोड' के नाम से पुकारने लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ समय बाद ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे थे। सड़क की सतह उखड़ना, बीच से दरारें पड़ना और कई स्थानों पर धंसाव जैसी समस्याएं सामने आने लगी थीं। इसके बावजूद संबंधित विभाग और निर्माण एजेंसी ने स्थायी समाधान के बजाय केवल औपचारिक मरम्मत कर मामले को दबाने का प्रयास किया।

8 से 9 किलोमीटर हिस्सा पूरी तरह जर्जर

क्षेत्रवासियों के अनुसार वर्तमान में सड़क का करीब 8 से 9 किलोमीटर हिस्सा अत्यंत खराब स्थिति में पहुंच चुका है। कई स्थानों पर सड़क लगभग 6 इंच तक धंस गई है, जबकि बीच सड़क में चौड़ी दरारें बन चुकी हैं। इन दरारों में दोपहिया वाहनों के पहिए फंसने से दुर्घटनाओं की आशंका लगातार बनी रहती है। देपालपुर-बनेडिया मार्ग पर बड़े और छोटे तालाब के बीच सड़क का हिस्सा बीच से धंस चुका है। वहीं बनेडिया गांव के भीतर पांच प्रमुख ब्लैक स्पॉट तथा बनेडिया से अटाहेड़ा के बीच कई अन्य खतरनाक स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां हर समय हादसे का खतरा बना रहता है।

ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के आरोप

स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निर्माण एजेंसी तथा विभागीय इंजीनियरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरपंच प्रतिनिधि बाबूलाल पटेल, पूर्व सरपंच धर्मराज पटेल, जगदीश पटेल, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष महेश पटेल, महेश गांधी, गजानंद मुकाती, जानकीलाल पटेल, मुरारीलाल टंकालिया, बलराम सेक्रेटरी, प्रकाश पटेल, संदीप जैन, मुसव्वर मंसूरी, गोकुल सिंह पवार, अर्जुन सिंह पवार, लाखनसिंह दरबार सहित अनेक ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की वास्तविक खामियों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि गारंटी अवधि के दौरान केवल दिखावटी मरम्मत की जाती रही। स्थायी सुधार के स्थान पर जगह-जगह डामर डालकर खानापूर्ति की गई, ताकि सड़क की वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके। आरोप यह भी है कि गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया को कमजोर रखकर निर्माण एजेंसी को लाभ पहुंचाया गया।

सुरक्षा इंतजाम नदारद, हर पल हादसे का खतरा

क्षेत्रवासियों के अनुसार सड़क के ब्लैक स्पॉट वाले हिस्सों में न तो चेतावनी संकेतक लगाए गए हैं और न ही रेडियम मार्किंग, स्पीड ब्रेकर अथवा सुरक्षा बैरिकेड्स की व्यवस्था की गई है। कई स्थानों पर सड़क का एक हिस्सा धंस चुका है जबकि दूसरा हिस्सा ऊपर उभर गया है, जिससे तेज गति से गुजरने वाले वाहन अचानक असंतुलित हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग पर दुर्घटनाएं अब आम हो चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

रविवार को फिर हुआ हादसा

रविवार को इसी मार्ग पर दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों चालक घायल हो गए, जिनमें एक युवक को गंभीर चोटें आईं। राहगीरों की मदद से घायलों को उपचार के लिए देपालपुर अस्पताल पहुंचाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति और असमान सतह लगातार हो रही दुर्घटनाओं की प्रमुख वजह है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की अत्यधिक खराब स्थिति के कारण गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई मामलों में रास्ते में ही प्रसव होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी कारण लोगों ने इस मार्ग को व्यंग्यात्मक रूप से 'डिलीवरी रोड' कहना शुरू कर दिया है। यात्रियों का कहना है कि लगातार झटकों के कारण कमर दर्द, रीढ़ संबंधी समस्याएं और स्लिप डिस्क जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं। एम्बुलेंस सेवाओं को भी इस मार्ग पर आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। वाहन चालक रशीद खान, मोहन सोलंकी और रामचंद्र जाटव ने बताया कि महज नौ किलोमीटर की दूरी तय करने में 25 मिनट से अधिक समय लग रहा है।

2028 सिंहस्थ को लेकर बढ़ी चिंता

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि वर्ष 2028 के सिंहस्थ महापर्व के दौरान इस मार्ग पर यातायात का दबाव कई गुना बढ़ जाएगा। यदि समय रहते सड़क का तकनीकी सुधार नहीं किया गया तो बड़े हादसों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचेगा मामला

लगातार अनदेखी से नाराज क्षेत्रवासियों ने अब मामले को उच्च स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा अन्य जांच एजेंसियों को दस्तावेजों सहित विस्तृत शिकायत भेजी जाएगी।

ग्रामीणों की प्रमुख मांगें

- सड़क की उच्चस्तरीय एवं स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए।
- सभी ब्लैक स्पॉट्स पर तत्काल सुरक्षा उपाय किए जाएं।
- निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कार्रवाई हो।
- दोषी निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए।

बनेड़िया तालाब पर बढ़ता संकटः जलकुंभी, अतिक्रमण और उपेक्षा के बीच सिमट रही ऐतिहासिक धरोहर

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। प्रदेश के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जलाशयों में शुमार बनेड़िया तालाब इन दिनों गंभीर अस्तित्व संकट से जूझ रहा है। लगभग 1800 एकड़ क्षेत्र में फैला यह विशाल तालाब जलकुंभी की मोटी परत, बढ़ते अतिक्रमण और विभागीय उदासीनता के कारण धीरे-धीरे अपना मूल स्वरूप खोता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कभी जल से लबालब रहने वाला यह जलाशय अब कई स्थानों पर दलदली भूमि और नाले जैसी स्थिति में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। बनेड़िया रोड स्थित वाटर प्वाइंट से लेकर ऐतिहासिक घाटों और छोटे तालाब क्षेत्र तक जलकुंभी का व्यापक फैलाव हो चुका है। जलकुंभी की मोटी परत ने जल क्षेत्र को लगभग पूरी तरह ढंक लिया है, जिससे न केवल जल संरक्षण प्रभावित हो रहा है, बल्कि तालाब की जैव विविधता और पर्यावरणीय संतुलन पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

अतिक्रमण और अवैध भराव ने बढ़ाई चिंता

ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब की भूमि पर भू-माफियाओं की नजरें टिक चुकी हैं। कई स्थानों पर अवैध रूप से मिट्टी और मलबा डालकर भराव किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ क्षेत्रों का निजी उपयोग भी किया जा रहा है तथा जमीन को किराए पर देने जैसी गतिविधियों की चर्चाएं भी ग्रामीण अंचल में सुनाई दे रही हैं। तालाब से जुड़ा छोटा तालाब, जो बिरगोदा रोड तक फैला हुआ है, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में शामिल है। यहां जलकुंभी का इतना घना फैलाव हो चुका है कि पहली नजर में यह क्षेत्र जलाशय के बजाय कृषि भूमि जैसा दिखाई देता है।

इतिहास और विरासत का जीवंत प्रतीक

बनेड़िया तालाब केवल जल स्रोत नहीं, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। जनश्रुतियों और स्थानीय इतिहास के अनुसार इसका निर्माण राजा देवपाल द्वारा कराया गया था। तालाब के किनारे बने काले एरन पत्थरों के प्राचीन घाट आज भी इसकी गौरवशाली विरासत की गवाही देते हैं। एक समय यह स्थल धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। दूर-दराज से आने वाली जमातों के हाथियों को भी यहां स्नान कराया जाता था। तालाब किनारे स्थित प्राचीन ईंट निर्मित कुंडी का निर्माण माता अहिल्याबाई होल्कर द्वारा कराया गया था, जबकि समीप स्थित शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग भी उनके संरक्षण और आस्था से जुड़ा माना जाता है।

खत्म होती जा रही पारंपरिक आजीविका

बनेड़िया तालाब भोई समाज सहित अनेक परिवारों की आजीविका का आधार रहा है। यहां वर्षों तक मछली पालन और बड़े आकार के स्वादिष्ट सिंघाड़ों की खेती होती रही, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आय प्राप्त होती थी। लेकिन पिछले डेढ़-दो दशकों में जलाशय की बिगड़ती स्थिति के कारण ये पारंपरिक गतिविधियां लगभग समाप्त हो चुकी हैं। जहां कभी मछुआरों की नावें और सिंघाड़ा उत्पादकों की गतिविधियां दिखाई देती थीं, वहां आज जलकुंभी का साम्राज्य नजर आता है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि एक पारंपरिक जीवनशैली भी धीरे-धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही है।

विभागीय उदासीनता पर उठ रहे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि जल संसाधन विभाग के अधीन होने के बावजूद तालाब के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए कोई प्रभावी अभियान नजर नहीं आता। समय रहते जलकुंभी हटाने, गहरीकरण कराने, अतिक्रमण रोकने और जल प्रवाह को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, जिसके कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय नागरिक संदीप जैन का कहना है कि यह जलाशय कभी क्षेत्र की जीवनरेखा माना जाता था और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रुपये का आर्थिक एवं पर्यावरणीय मूल्य रखता है। यदि शीघ्र ही संरक्षण और पुनर्स्थापन की व्यापक योजना नहीं बनाई गई तो आने वाली पीढ़ियां इस ऐतिहासिक धरोहर को केवल पुस्तकों और स्मृतियों में ही देख पाएंगी।

प्रमुख तथ्य

- लगभग 1800 एकड़ क्षेत्र में फैला है बनेड़िया तालाब।
- जलकुंभी के कारण अधिकांश जल क्षेत्र प्रभावित।
- छोटे तालाब और ऐतिहासिक घाट क्षेत्र पर संकट गहराया।
- अतिक्रमण और अवैध भराव के आरोपों से बढ़ी चिंता।
- मछली पालन और सिंघाड़ा उत्पादन जैसी पारंपरिक गतिविधियां बंद।
- जल संसाधन विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल।
- संरक्षण नहीं हुआ तो ऐतिहासिक जलाशय का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।

हरे धनिए ने बढ़ाई किसानों की चिंता, लागत भी नहीं निकलने से फसल भेड़-बकरियों को खिलाने की नौबत

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

इंदौर। जिले के किसानों को इस बार हरे धनिए की फसल में भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बेहतर मुनाफे की उम्मीद में रबी फसल की कटाई के बाद खाली पड़ी भूमि में बड़ी संख्या में किसानों ने हरे धनिए की बोवनी की थी, लेकिन जब फसल तैयार होकर बाजार में पहुंची तो दामों में अचानक आई गिरावट ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। स्थिति यह है कि कई किसानों को उपज बेचने पर लागत तक नहीं मिल रही है, जिसके चलते वे मजबूरी में खेतों में खड़ी धनिए की फसल को उखाड़कर भेड़-बकरियों को खिलाने पर विवश हैं। जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों अनेक खेतों में हरे-भरे धनिए की फसल पशुओं का चारा बनती दिखाई दे रही है। किसानों का कहना है कि बोवनी के समय बाजार में धनिए के अच्छे भाव मिल रहे थे। इसी को देखते हुए उन्होंने बीज, खाद, सिंचाई और मजदूरी पर खर्च कर फसल तैयार की, लेकिन उत्पादन आने तक बाजार में आवक बढ़ने से कीमतें लगातार नीचे आ गईं। ऐसे में फसल बेचने पर परिवहन और कटाई का खर्च भी निकलना मुश्किल हो रहा है। किसानों के अनुसार धनिए की खेती में प्रति बीघा हजारों रुपये की लागत आती है। बीज, उर्वरक, सिंचाई और श्रम पर किया

गया खर्च वापस नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। कई किसानों ने बताया कि यदि फसल की कटाई कर बाजार तक पहुंचाई जाए तो अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है, जबकि मंडियों में मिल रहे भाव लागत से भी कम हैं। इसलिए फसल को खेत में ही समाप्त करना अधिक व्यावहारिक विकल्प बन गया है। देपालपुर क्षेत्र के किसान लाखन गेहलोत, सीताराम गहलोत, लाखन सिंह दरबार, अर्जुन सिंह और गोकुल सिंह सहित अन्य किसानों ने बताया कि धनिए के गिरते दामों ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। किसानों का कहना है कि जिस फसल से आय की उम्मीद थी, वही अब घाटे का कारण बन गई है। कई किसानों ने खेतों में घूम रहे राजस्थान के भेड़-बकरी पालकों को फसल चराने की अनुमति दे दी है, ताकि खेत जल्दी साफ हो सकें और अगली फसल की तैयारी समय पर की जा सके।

मानसून पूर्व खेतों की तैयारी में जुटे किसान

इधर जिले में मानसून आगमन की संभावना को देखते हुए किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं। धनिए की फसल हटाने के बाद खेतों की जुताई और बखरनी का कार्य तेज हो गया है। किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से खेत तैयार कर रहे हैं ताकि अच्छी वर्षा होते ही सोयाबीन, मक्का, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बोवनी की जा सके। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन के कारण

कई बार नकदी फसलों के भाव अचानक गिर जाते हैं। ऐसे में किसानों को फसल विविधीकरण और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए खेती की योजना बनानी चाहिए। हालांकि किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत और अनिश्चित बाजार व्यवस्था के बीच खेती लगातार जोखिम भरा व्यवसाय बनती जा रही है।

उचित मूल्य नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी

किसानों का आरोप है कि कृषि उत्पादन बढ़ने के बावजूद उन्हें उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। एक ओर बीज, खाद, डीजल और मजदूरी की लागत लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर बाजार में फसलों के दाम गिरने से उनकी आय प्रभावित हो रही है। किसानों ने शासन से मांग की है कि सब्जी एवं उद्यानिकी फसलों के लिए भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उत्पादकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके और उन्हें फसल नष्ट करने जैसी परिस्थितियों का सामना न करना पड़े। धनिए के गिरते दामों और बढ़ती लागत के बीच इंदौर जिले के अनेक किसान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मानसून से पहले खेतों को खाली करने की मजबूरी ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। किसान अब अच्छी बारिश और खरीफ फसलों से बेहतर उत्पादन की उम्मीद लगाए हुए हैं, ताकि पिछले नुकसान की कुछ भरपाई हो सके।

फर्जी महिला को खड़ा कर करा ली रजिस्ट्री, किसान की जमीन हड़पने की साजिश; आरोपी के खिलाफ एफआईआर

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

उन्हेल। ग्राम नवादा में एक किसान की कृषि भूमि को कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों और प्रतिरूपण के जरिए अपने नाम कराने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। शिकायत और जांच के बाद सामने आया कि वर्षों पहले मृत हो चुकी महिला के नाम पर किसी अन्य महिला को उप पंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत कर भूमि की रजिस्ट्री करा ली गई। मामले में पुलिस ने संबंधित महिला के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्राम नवादा निवासी किसान अर्जुन पिता रामलाल पिछले करीब 50 वर्षों से सर्वे नंबर 318 स्थित भूमि पर खेती-बाड़ी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। किसान का आरोप है कि कुछ लोगों ने उनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर उक्त भूमि को हड़पने की साजिश रची। इसके तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि की रजिस्ट्री कराने का प्रयास किया गया। पीड़ित किसान ने मामले की शिकायत उन्हेल थाना, रजिस्ट्रार कार्यालय तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की थी। शिकायत में बताया गया कि 14 मार्च 2026 को मकड़ावन निवासी कविता पिता राकेश द्वारा भूमि स्वामिनी मानीबाई पति शैतानमल जैन के स्थान पर किसी अन्य महिला को प्रस्तुत कर उप पंजीयक कार्यालय में रजिस्ट्री कराई गई। जबकि वास्तविक भूमि स्वामिनी मानीबाई की वर्ष 1980 में ही मृत्यु हो चुकी थी। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि रजिस्ट्री प्रक्रिया में उपयोग किए गए दस्तावेज और पहचान संबंधी रिकॉर्ड संदिग्ध पाए गए। आरोप है कि मृत महिला के नाम पर फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार कर भूमि का अवैध हस्तांतरण कराया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले

की जांच शुरू की और प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी तथा प्रतिरूपण के तथ्य पाए जाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया।

उप पंजीयक कार्यालय की शिकायत पर कार्रवाई

पुलिस के अनुसार नागदा उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आवेदन में भी उल्लेख किया गया था कि सर्वे नंबर 318 की भूमि मानीबाई पति शैतानमल जैन के नाम दर्ज है, जिनका कई वर्ष पूर्व निधन हो चुका है। इसके बावजूद किसी अन्य महिला ने स्वयं को मानीबाई बताकर रजिस्ट्री करा ली। जांच में आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों की सत्यता पर भी सवाल खड़े हुए हैं।

आरोपी महिला की तलाश जारी

उन्हेल थाना पुलिस ने धोखाधड़ी एवं कूटरचना से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब रजिस्ट्री में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। फोटो एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आरोपी महिला की तलाश की जा रही है।

इनका कहना है:-

'नागदा उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि मृत महिला के नाम पर किसी अन्य महिला ने स्वयं को प्रस्तुत कर भूमि की रजिस्ट्री कराई थी। दस्तावेजों में भी अनियमितताएं सामने आई हैं। मामले में धोखाधड़ी संबंधी धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी महिला की तलाश की जा रही है।'

– संतोष चौहान, थाना प्रभारी, उन्हेल

रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प नहीं, नियमित रक्तदान करें : खान

प्रेरणादायी ग़ज़ल ने बांधा समां, रक्तदान के प्रति जागरूकता का दिया संदेश

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर तहसील विधिक सेवा समिति, देपालपुर के तत्वावधान में सम्मान एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वैच्छिक रक्तदान के माध्यम से जरूरतमंदों को जीवनदान देने वाले रक्तवीरों का सम्मान किया गया तथा रक्तदान के महत्व पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान ने कहा कि रक्तदान केवल चिकित्सकीय आवश्यकता नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का सर्वोच्च उदाहरण है। एक यूनिट रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। रक्तदाता वह अनमोल व्यक्तित्व है, जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अजनबी के जीवन में आशा का संचार करता है। उन्होंने कहा कि रक्त का कोई कृत्रिम विकल्प उपलब्ध नहीं है। ऐसे में स्वैच्छिक रक्तदान ही जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है। प्रत्येक स्वस्थ नागरिक को नियमित रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए, ताकि किसी भी मरीज को रक्त के अभाव में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने युवाओं से रक्तदान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट रक्तदान सेवाओं के लिए रक्त मित्र दौलत नागर, देपालपुर सर्विस हेल्प फाउंडेशन के अध्यक्ष मोइनुद्दीन, रक्त सेवा संघ गौतमपुरा के राहुल बैरागी एवं राहुल तंवर तथा 50 से अधिक बार रक्तदान कर चुके नितिन जैन (सीजीएसटी इंस्पेक्टर) को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्मानित रक्तदाताओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए अधिक से अधिक लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम को अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष दिलीप डाबी, अधिवक्ता योगेंद्र यादव एवं एडीपीओ विक्रम राव बेन ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने रक्तदाताओं को समाज का वास्तविक नायक बताते हुए कहा कि उनका योगदान अनेक परिवारों के लिए आशा और जीवन का आधार बनता है। कार्यक्रम का विशेष आकर्षण जिला न्यायाधीश हिदायत उल्ला खान द्वारा रक्तदान की महत्ता पर प्रस्तुत प्रेरणादायी ग़ज़ल रही। उनकी प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह को भावुक करते हुए रक्तदान के प्रति सकारात्मक संदेश दिया।

सम्पादकीय

गृहिणी राष्ट्रनिर्माता है तो हिंसा की शिकार क्यों?

भारतीय समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने के दावे लंबे समय से किए जाते रहे हैं। उन्हें 'आधी आबादी' और विकास की समान भागीदार कहा जाता है। शिक्षा, रोजगार, राजनीति और नेतृत्व के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई जाती हैं। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की प्रतिबद्धता जताई जाती है। सरकारें महिला सशक्तीकरण को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करती हैं और समाज भी महिलाओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करता है। लेकिन इन सबके बीच कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जो हमें इस सशक्तीकरण के वास्तविक स्वरूप पर पुनर्विचार करने के लिए विवश करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने गृहिणियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें 'नेशन बिल्डर' अर्थात् राष्ट्रनिर्माता कहा। न्यायालय ने यह भी माना कि घरेलू कार्यों और परिवार की देखभाल में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले श्रम का आर्थिक मूल्य है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़े बताते हैं कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रत्येक चौथी तथा शहरी क्षेत्रों की प्रत्येक छठी महिला किसी न किसी रूप में हिंसा का शिकार होती है। यह स्थिति एक गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। जिस महिला को राष्ट्रनिर्माता कहा जा रहा है, वही महिला अपने घर, परिवार और समाज में असुरक्षा और हिंसा का सामना करने को विवश है। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय भारतीय समाज में महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। सदियों से गृहिणियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को केवल कर्तव्य या प्रेम का विस्तार मान लिया गया। घर की सफाई, भोजन बनाना, बच्चों का पालन-पोषण, बुजुर्गों की सेवा, परिवार के स्वास्थ्य और संस्कारों की रक्षा, घरेलू प्रबंधन और सामाजिक संबंधों का निर्वहन-इन सभी कार्यों को महिलाओं का स्वाभाविक दायित्व माना गया। परिणामस्वरूप उनके श्रम को कभी आर्थिक दृष्टि से नहीं आंका गया। वास्तव में यदि किसी परिवार में गृहिणी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए, तो उस पर भारी आर्थिक व्यय आएगा। इसके बावजूद गृहिणी के श्रम को न तो वेतन मिलता है और न ही सामाजिक मान्यता। वह चौबीस घंटे और वर्ष के तीन सौ पैंसठ दिन कार्यरत रहती है। उसका कोई अवकाश नहीं होता, कोई पदोन्नति नहीं होती और कोई सेवानिवृत्ति नहीं होती। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना कि गृहिणी केवल परिवार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी योगदान देती है, सामाजिक चेतना को नई दिशा देने वाला विचार है। न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले में गृहिणी की सेवाओं का मूल्यांकन न्यूनतम 30 हजार रुपये प्रतिमाह के आधार पर करने की बात कही। यह केवल एक कानूनी निर्णय नहीं, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता को चुनौती है जो घरेलू श्रम को महत्वहीन समझती रही है। वास्तव में महिलाओं का यह अदृश्य श्रम देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यदि इस श्रम का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए और उसे सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में शामिल किया जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर काफी बदल सकती है। लेकिन इसी संदर्भ में दूसरा पक्ष और भी अधिक चिंता पैदा करता है। जिस महिला के योगदान को सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्र निर्माण का आधार मान रहा है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने सफल 12 वर्ष के रिकार्ड प्रधानमंत्री शासन की आयोजनाओं के अवसर पर महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सम्मान की अधिकारी मान कर रहे हैं, क्या उसे वह सम्मान, सुरक्षा और गरिमा प्राप्त है जिसकी वह अधिकारी है? दुर्भाग्य से इसका उत्तर संतोषजनक नहीं है।

बच्चे, युवा पीढ़ी और आधुनिक ज्ञान का संतुलन

अशोक मेहता, इंदौर
(पत्रकार, वास्तुविद् एवं पर्यावरणविद्)

मैं बच्चों और युवाओं को अपना सबसे सच्चा मित्र मानता हूँ, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की बात को समझता है, उस पर विचार करता है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इसलिए आज मैं अपने युवा मित्रों से कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहता हूँ, जो उनके जीवन को सही दिशा देने में सहायक हो सकती हैं। कुछ दशक पहले की शिक्षा व्यवस्था पर यदि हम दृष्टि डालें तो पाएंगे कि विद्यालय केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने का स्थान नहीं होते थे। वहाँ पढ़ाई के साथ-साथ व्यायाम, खेलकूद, हस्तकला, नैतिक शिक्षा, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अनुशासन का भी प्रशिक्षण दिया जाता था। उस समय शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक सुसंस्कृत, चरित्रवान और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना था। वर्तमान समय में शिक्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को अनेक सुविधाएँ प्रदान की हैं। आज किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में उपलब्ध हो जाता है। यह सुविधा उपयोगी तो है, किन्तु यदि हम अपनी सोचने-समझने की क्षमता को छोड़कर केवल मशीनों पर निर्भर हो जाएँ, तो यह हमारी बौद्धिक शक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। युवा मित्रों, ज्ञान का वास्तविक स्रोत आपका स्वयं का चिंतन, अध्ययन और अनुभव है। यदि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बिना विचार किए केवल तकनीकी साधनों से प्राप्त करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी स्मरण शक्ति, तर्क क्षमता और मौलिक सोच कमजोर पड़ सकती है। इसलिए आधुनिक साधनों का उपयोग अवश्य करें, परंतु उन्हें अपने ज्ञान का आधार नहीं, बल्कि सहयोगी बनाकर रखें।आज उच्च शिक्षा निरंतर महंगी होती जा रही है। ऐसे समय में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है। जीवन में सफलता के लिए परिश्रम, अनुशासन, व्यवहार-कुशलता, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों का होना भी उतना ही आवश्यक है। घर के छोटे-बड़े कार्यों में सहयोग करना, परिवार की जिम्मेदारियों को समझना और श्रम का सम्मान करना जीवन की सबसे बड़ी पाठशाला है। प्रकृति मनुष्य की सबसे बड़ी गुरु है। प्रातःकाल शीघ्र उठना, उगते हुए सूर्य की लालिमा को निहारना, शीतल और स्वच्छ वायु का आनंद लेना, पक्षियों का मधुर कलरव सुनना तथा हरियाली के बीच कुछ समय बिताना तन और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सुबह का समय अध्ययन, चिंतन और आत्मविकास के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस समय अर्जित किया गया ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। दुर्भाग्यवश कुछ बच्चे और किशोर छोटी आयु में ही गलत संगति के प्रभाव में आ जाते हैं। तंबाकू, धूम्रपान, नशा, असत्य भाषण, चोरी अथवा अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें धीरे-धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। प्रारंभ में ये बातें छोटी प्रतीत होती हैं, परंतु समय के साथ यही आदतें उनके भविष्य को अंधकारमय बना सकती हैं। इसलिए युवाओं को सदैव अच्छी संगति का चयन करना चाहिए और अपने चरित्र की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। यदि हम पर्यावरण की बात करें तो सामान्यतः हमारा ध्यान पेड़-पौधों, जल, वायु और भूमि की ओर जाता है। वास्तव में पर्यावरण दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश सम्मिलित हैं। दूसरा सामाजिक पर्यावरण, जिसे हम अपने व्यवहार, विचार और वाणी से निर्मित करते हैं। जैसे प्रदूषित जल और दूषित वायु मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, वैसे ही कटु वचन, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, असत्य और भ्रष्ट आचरण सामाजिक वातावरण को दूषित कर देते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने आसपास ऐसा वातावरण निर्मित करे, जहाँ प्रेम, सहयोग, सद्भाव, सत्य और मानवता का वास हो। प्रत्येक युवा में बाँटने और सहयोग करने की भावना होना आवश्यक है। ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, प्रेम बाँटने से रिश्ते मजबूत होते हैं और सहयोग से समाज प्रगति करता है। माता-पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। जो व्यक्ति अपने मार्गदर्शकों का सम्मान करता है, उसके लिए सफलता के मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाते हैं। जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएँगी। कभी परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी तो कभी प्रतिकूल। किन्तु विपरीत परिस्थितियों से घबराने के स्थान पर उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले कार्यों को भी संभव बना देती है। अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखिए कि आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अंत में मैं अपने युवा मित्रों को दो जीवन-मंत्र देना चाहता हूँ–

'अन्याय करना नहीं और अन्याय सहना नहीं।' 'ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है।'

सत्य, परिश्रम, स्वाभिमान, अनुशासन और आत्मविश्वास को अपना जीवन आधार बनाइए। प्रकृति से प्रेम कीजिए, अपने माता-पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए, समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझिए और अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं को पहचानिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का जागरूक, संस्कारित और परिश्रमी युवा ही कल के समृद्ध, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण करेगा।

जय हिन्द! जय भारत!

खाद की बढ़ी कीमतों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, एक साल में 27 से 48 प्रतिशत तक महंगे हुए उर्वरक

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

इंदौर। कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ती लागत किसानों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। पेट्रोल-डीजल के दामों में वृद्धि के बाद अब रासायनिक उर्वरकों की कीमतों में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पिछले एक वर्ष में प्रमुख उर्वरकों के दाम 27 से 48 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं, जिससे खेती की लागत में भारी इजाफा हुआ है। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और उपज के अपेक्षित मूल्य नहीं मिलने से खेती लाभ के बजाय घाटे का सौदा बनती जा रही है।

एनपीके 650 रुपये प्रति बोरी महंगा

कृषि विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 की तुलना में वर्ष 2026 में कई प्रमुख उर्वरकों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) का मूल्य 380 रुपये प्रति बोरी से बढ़कर 565 रुपये हो गया है, जो करीब 48.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वहीं एनपीके (12:32:16) खाद 1800 रुपये से बढ़कर 2450 रुपये प्रति बोरी पहुंच गई है। पोटाश के दाम भी 1550 रुपये से बढ़कर 1975 रुपये प्रति बोरी हो गए हैं। हालांकि यूरिया और डीएपी की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कृषि आदानों की लागत भी बढ़ी

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल खाद ही नवीं, बल्कि खेती से जुड़े लगभग सभी कृषि आदान महंगे हो चुके हैं। कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाइयां, डीजल-पेट्रोल और मजदूरी दरों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके कारण किसानों की उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है, जबकि उनकी उपज को उस अनुपात में बाजार मूल्य नहीं मिल पा रहा है।

लागत और आय के बीच बढ़ रही खाई

किसानों का कहना है कि खाद, डीजल, मजदूरी और अन्य कृषि खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि गेहूं, सोयाबीन, चना, मूंग, मटर, लहसुन, प्याज और आलू जैसी फसलों के दाम लगभग स्थिर बने हुए हैं। लागत और आमदनी के बीच बढ़ता अंतर किसानों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है। कृषि विशेषज्ञों और किसानों ने सरकार से मांग की है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत एसएसपी, एनपीके और पोटाश जैसे उर्वरकों पर विशेष सब्सिडी प्रदान की जाए। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का निर्धारण वास्तविक उत्पादन लागत को ध्यान में रखकर किया जाए। उनका मानना है कि यदि खेती की बढ़ती लागत पर नियंत्रण नहीं पाया गया और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिला तो कृषि संकट और गहरा सकता है, जिसका असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

किसानों की जुबानी

'फास्फेट और एनपीके खाद की 10 से 12 बोरियां लगती हैं। इस बार खाद के दाम काफी बढ़ गए हैं। डीजल और सोयाबीन बीज के भाव भी बढ़े हैं। ऐसे में खेती अब लाभ का नहीं, घाटे का धंधा बनती जा रही है।

– विष्णु प्रसाद चौधरी, किसान

'इस वर्ष सुपर फास्फेट और इफको एनपीके खाद के दामों में वृद्धि हुई है। संस्था के सदस्यों को बढ़ी हुई दरों पर ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल संस्था में खाद का स्टॉक उपलब्ध नहीं है।'

– भवानी शंकर चौधरी, प्रबंधक, सेवा सहकारी संस्था बनेड़िया

उज्जैन का रंगमंच मध्य प्रदेश में सबसे सशक्त, वरिष्ठ रंगकर्मी सतीश दवे को मिलेगा देश का सर्वोच्च नाट्य सम्मान

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

उज्जैन, कीर्ति राणा । शहर के संस्कृतिकर्मियों के लिये तो यह खुशी की बात है कि वरिष्ठ रंगकर्मी सतीश दवे जी को देश के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी अवॉर्ड के लिए चयनित किए जाने की घोषणा की गई है। उज्जैन में यह सम्मान पाने वाले दवे जी तीसरे रंगकर्मी हैं। उनसे पहले प्रभात कुमार भट्टाचार्य (रंगमंच) और ओम प्रकाश शर्मा (संगीत) सम्मानित हो चुके हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दवे जी का चयन होना न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि उज्जैन और पूरे प्रदेश के रंगमंच के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। उन्हें उज्जैन शहर की तरफ से बधाई देने के

साथ ही जब पूछा कि आज उज्जैन के रंगमंच को आप कहां देखते हैं? उनका कहना था रंगकर्मियों और दर्शकों के मान से मध्य प्रदेश में उज्जैन का रंगमंच सबसे सशक्त है। फिर हिंदी रंगमंच अन्य भाषाओं के रंगमंच जितनी ख्याति क्यों नहीं प्राप्त कर सका, दवे जी ने स्वीकारा कि मराठी, गुजराती, तमिल आदि क्षेत्रीय भाषाओं का रंगमंच इसलिए आगे है कि उन्होंने परिवारों को जोड़ा है जबकि हिंदी रंगमंच स्वतंत्रता का पक्षधर रहा है। मुंबई में नाटकों के टिकट पांच सौ से पांच हजार तक भी हो तो दर्शक खरीद लेते हैं। यहां तो 'हमारे राम' के लिए भी दर्शक टिकट के लिये लालायित रहते हैं कि उसमें कलाकार महत्वपूर्ण हैं।हिंदी नाटकों के प्रति दर्शकों में बाकी भाषाओं के रंगमंच जैसी जागरुकता की जरूरत है। मूल रूप से बड़नगर निवासी सतीश दवे का 10-12 वर्ष की उम्र में नाटकों से तब जुड़ाव हो गया था जब गणेशोत्सव के लिये उनके घर पर नाटकों की रिहर्सल होती थी।1975 में रायपुर में जब एमके रैना ने वर्कशाप आयोजित की तो उसमें शामिल हुए। अब तक 60 नाटक लिखने के साथ ही लगभग इतने ही नाटकों का निर्देशन कर चुके हैं।

उनके लिखे-निर्देशित बेहद चर्चित रहे नाटक

राजा भाऊ महाकाल के जीवन आधारित 'एक भूला हुआ सेनानी' और आज के युवा का अपने बुजुर्गों के प्रति व्यवहार आधारित 'कतरा-कतरा जिंदगी' उनके चर्चित नाटक रहे हैं।'जयति पार्श्वनाथ' नाटक (लाइट एंड शो) देश के सारे जैन तीर्थों में खेला जा चुका है। दवे जी को यह सम्मान प्रदर्शन कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जो संगीत, नृत्य और नाटक के प्रख्यात कलाकारों को उनके विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है।

हर साल 'बाल मंच' और 'परिष्कृति' शिविर

रंगकर्मी दवे हर साल बच्चों के लिए 'बालमंच' नाट्य शिविर (1985 से) और 14 वर्ष से अधिक वालों के लिए 'परिष्कृति' शिविर (2013 से) का निशुल्क आयोजन कर रहे हैं। यह भी संयोग है कि पहले जो कई बच्चे बाल मंच में नाट्यकला सीखे वो अब पालक के रूप में परिष्कृति में भाग ले रहे हैं।

बाजार में उतरा खास स्वाद वाला आम उत्तर प्रदेश के परी आम ने राजपुरा के बागान का बड़ा दिया उत्साह

अमरापुरी अमराई, संसेशन ओर बगीचे की महारानी परी का रंग है सतरंगी स्वाद लाजवाब चमक इंद्रधनुष सी

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

अमझेरा, जितेंद्र चौहान । नगर के समीप्थ ग्राम राजपुरा आम बगीचे में अमरापुरी, सेंसशन, रत्नागिरी आकूष, मल्लीका,चौसा जैसे कई प्रजातियों के आम से प्रसिद्ध अमरापुरी अमराई बगीचे मैं ईस बार एक नई किस्म की आम प्रजाति चर्चा का केंद्र बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की चर्चित परी अपने स्वाद और सतरंगी कलर से बगीचे मे इठला रही है। वहीं ढाई से तीन किलो वजनी अमरापुरी आम भी बगीचे में मौजूद होकर काफी चर्चित है । ऊंची बाजार कीमत के कारण यह आम बगीचे की नई उम्मीद बनकर उभरा है।छः सो से एक हजार रुपए तक की बाजार कीमत वाले आम इस बगान में मिल रहे हैं। आम खरीदी के लिए मध्य प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों से लोग बगीचे में आ रहे हैं। जगदीश आगलेचा ने बताया कि बड़े भाई रामेश्वर आगलेचा के साथ भारत भ्रमण कर आम की नई-नई किस्म का पता किया। जिसमें भारत का प्रसिद्ध अमरापुरी, महाराष्ट्र का रत्नागिरी आकुश,उत्तर प्रदेश का परी, पंचमढ़ी का मल्लिका, हिमाचल प्रदेश,बिहार का चौसा,हिमसागर का सब्जा, पश्चिम बंगाल का माल्दा, लखनऊ का लंगड़ा,प्रयागराज का फजली ओर जूनागढ़ का केसर आदि सामिल है। इसके अलावा विदेशी किस्म के रेड आइवरी, रेड पालमर, केंट ,एप्पल मैंगो ,बनाना मैंगो, ब्लैक कस्तूरी, अरुणिमां जैसे कुल मिलाकर 130 से अधिक किस्म के आम के पेड़ बगीचे में मौजूद है। किसान की दो दशकों की कड़ी मेहनत के बाद 23 बीघा के बगीचे में 968 आम के पेड़ हैं तथा 750 से अधिक पौधे लगाए है। देखने में यह सब आसान लगता है परंतु कई मूलभूत सुविधाओं के अभाव मे किसान की कई वर्षों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। वर्ष दो हजार चार बगान के शुरुआती दिनों में भारत कई राज्यों से आम की गुठलियां एकत्रित कर बुआई कर बिना किसी रासायनिक दवाई के उपयोग किए पूर्ण रूप से प्राकृतिक तरीका अपना कर उन्हें नन्हें पौधों का स्वरूप दिया। उस समय पानी की काफी किल्लत थी लेकिन किसान पीछे नहीं हटे और पानी की होद से प्लास्टिक की थैलियों में पानी भरकर उसमें एक छोटा सुराग बनाकर आम के नन्हे पौधों के ऊपर टांग कर पानी पिलाया करते थे। उन्हें अब उसी कड़ी मेहनत का फल मिला ओर आज 130 से अधिक प्रजातियों का रकबा खड़ा किया है। इतनी सारी किस्म के आम वाला जिले का पहला बगीचा बनकर उभरा है। किसान ने बताया कि हमारे स्वर्गीय पिताजी भी पर्यावरण प्रेमी थे हम पिता जी ओर सतगुरु सुखराम जी महाराज से प्रेरणा लेकर पारंपरिक खेती को त्याग कर आम की खेती के लिए बगीचा बनाया जिससे लोग विशैला आम खाने से भी बच रहे हैं ।ऐसे किसान सराहना करना उचित होगा की जिन्होने न सिर्फ परंपरागत खेती से हटकर फलों के राजा आम का बगीचा बनाया बल्की पर्यावरण को बढ़ावा भी दिया। ओर साथ ही हजारों पौधे लोगों मुफ्त में बाटकर पौधे लगाने के लिए जागरूकता का भी काम किया हैं।

देपालपुर में 15 से 17 जून तक लगेगा जनकल्याण शिविर, छूटे पात्र हितग्राहियों का होगा पंजीयन

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सुशासन एवं स्वराज के संकल्प को साकार करने तथा विकसित मध्यप्रदेश के लक्ष्य की दिशा में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से वंचित पात्र नागरिकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जनपद पंचायत देपालपुर परिसर में 15, 16 एवं 17 जून 2026 को तीन दिवसीय खण्ड स्तरीय जनकल्याण शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगा। शासन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाले इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं से अभी तक वंचित रह गए पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उनका पंजीयन करना, लंबित आवेदनों का निराकरण करना तथा नागरिकों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। शिविर में केंद्र एवं राज्य शासन की प्रमुख हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। पात्र हितग्राहियों का मौके पर पंजीयन, स्वीकृति एवं लाभ वितरण की प्रक्रिया भी संचालित होगी। इसके साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित निराकरण का प्रयास करेंगे। जनपद पंचायत देपालपुर में आयोजित होने वाले इस खण्ड स्तरीय शिविर में राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय, खाद्य, स्वास्थ्य, श्रम, कृषि सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। शिविर स्थल पर विभागवार स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन एवं सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। शासन ने निर्देश दिए हैं कि शिविरों के माध्यम से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निराकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।

पीथमपुर में मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

पीथमपुर। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर के सतनाला क्षेत्र में एक संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने मूक-बधिर नाबालिग बालिका से कथित दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों को मिली। पुलिस के अनुसार सतनाला निवासी 20 वर्षीय युवक संदीप पिता संतोष उर्फ शेरू पर आरोप है कि उसने पड़ोस में रहने वाली मूक-बधिर नाबालिग बालिका के साथ कई बार यौन शोषण किया। परिजनों को इसकी जानकारी 3 जून को उस समय हुई जब उन्होंने बालिका की शारीरिक स्थिति में असामान्य परिवर्तन देखा। संदेह होने पर माता-पिता ने बालिका से इशारों के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया। पूछताछ के दौरान बालिका भावुक हो गई और कथित आरोपी की तस्वीर दिखाए जाने पर उसकी ओर इशारा कर पहचान की। परिजनों के अनुसार सामाजिक दबाव और बदनामी की आशंका के चलते प्रारंभ में वे शिकायत दर्ज नहीं करा सके। बाद में उन्होंने 11 जून को पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलते ही पीथमपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर के निर्देशन में मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया है। चूंकि पीड़िता मूक-बधिर है, इसलिए उसके

विधिसम्मत बयान दर्ज कराने के लिए सांकेतिक भाषा (साइन लैंग्वेज) विशेषज्ञ की सहायता ली जा रही है, ताकि जांच निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित तरीके से आगे बढ़ाई जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा रही हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

त्वरित कार्रवाई से मिली सराहना

संवेदनशील मामले में नगर पुलिस अधीक्षक रवि सोनेर के मार्गदर्शन में पीथमपुर पुलिस द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। शिकायत प्राप्त होने के बाद पुलिस ने बिना विलंब आरोपी को गिरफ्तार कर जांच प्रारंभ कर दी। साथ ही पीड़िता की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सहायता से कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

37 साल पुराना सहकारी समिति भवन जर्जर, राशन वितरण के बीच हादसे का खतरा

उजालिया स्थित सहकारी समिति भवन में पड़ी दरारें, जर्जर भवन में ही संचालित हो रही शासकीय उचित मूल्य की दुकान

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। तहसील मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर ग्राम उजालिया में स्थित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का भवन अब अपनी उम्र पूरी कर चुका है। वर्ष 1988 में निर्मित यह भवन वर्तमान में अत्यंत जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और कई हिस्सों में क्षति स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसके बावजूद इसी भवन में शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित की जा रही है, जहां प्रतिदिन ग्रामीण राशन, खाद एवं बीज लेने पहुंच रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही भवन की स्थिति को लेकर ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी समय भवन का कोई हिस्सा गिर सकता है, जिससे जनहानि की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारी अब तक भवन की मरम्मत या नए निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह सहकारी संस्था पांच गांवों को जोड़कर संचालित होती है, इसलिए यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान और उपभोक्ता पहुंचते हैं। ऐसे में जर्जर भवन में खाद्यान्न, खाद और बीज का भंडारण भी चुनौती बना हुआ है। भवन की खराब हालत के कारण सामग्री के सुरक्षित रखरखाव में भी दिक्कतें आ रही हैं।

ग्रामीणों ने जताई चिंता

ग्राम उजालिया एवं बानियाखेड़ी के ग्रामीणों ने बताया कि भवन की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। कई बार अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते नया भवन नहीं बनाया गया तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में गोकुल सिंह पवार, पूर्व सरपंच तकेे सिंह तोमर, पूर्व सरपंच दुलेसिंह दरबार, अर्जुन सिंह पवार, राजेंद्र सिंह पटेल, नरेंद्र विश्वकर्मा, लाखन सिंह गेहलोत और राजेंद्र सिंह दरबार सहित अन्य ग्रामीणों ने भवन के शीघ्र निर्माण की मांग की है।

नया भवन बनाने का प्रस्ताव भेजने की तैयारी

ग्रामीणों ने बताया कि भवन निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। उनका कहना है कि शासन की योजना के अंतर्गत नया भवन स्वीकृत कराया जा सकता है। पंचायत स्तर पर भी मनरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से भवन निर्माण की संभावना है। ग्रामीणों का कहना है कि संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजकर शीघ्र स्वीकृति दिलाई जानी चाहिए, ताकि किसानों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

सरपंच बोले- कलेक्टर को देंगे ज्ञापन

ग्राम पंचायत बानियाखेड़ी के सरपंच गोकुल सिंह पवार ने भवन की जर्जर स्थिति स्वीकार करते हुए कहा कि सहकारी समिति का भवन काफी पुराना हो चुका है और इसकी हालत चिंताजनक है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही यदि विधायक निधि या सांसद निधि से भवन निर्माण की कोई योजना स्वीकृत हुई है तो उसकी जानकारी विभाग से प्राप्त की जाएगी।

पांच गांवों की जरूरतों का केंद्र

उजालिया स्थित यह सहकारी संस्था पांच गांवों के किसानों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे में भवन की जर्जर स्थिति केवल एक गांव का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के हजारों हितग्राहियों की सुरक्षा और सुविधा से जुड़ा मुद्दा बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को किसी दुर्घटना का इंतजार करने के बजाय तत्काल कार्रवाई कर नए भवन के निर्माण की दिशा में पहल करनी चाहिए।

धुन की पक्की : हेमलता भोली बेन का बड़ा काम अपने दम पर तैयार किया मालवी का शब्दकोश

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

आगर मालवा , कीर्ति राणा। मालवी बोली के प्रचार-प्रसार में लगी रहने वाली हेमलता शर्मा 'भोली बेन' ने अपने दम पर मालवी भाषा का शब्दकोश तैयार करने का काम किया है। मालवी शब्दों का हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद वाले इस शब्दकोश में करीब साढ़े 5 हजार शब्द समाहित हैं। मूल रूप से आगर मालवा निवासी और खरगोन में वित्त विभाग में उप संचालक (वरिष्ठ कोषालय अधिकारी) पदस्थ भोली बेन ने चर्चा में कहा यह शब्दकोश तैयार करने से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मालवी शब्द जुटाने में सहयोग की अपील भी की थी, मालवी बोली में लोकोक्ति-मुहावरे वाली पांच हजार पुस्तकें प्रकाशन कराने के साथ स्कूलों में वितरित कर चुकी भोली बेन ने मालवी बोली में गालियों के संग्रह पर भी काम किया है। हाल ही में प्रकाशित इस शब्दकोश के लिये वे आगर में मालवी परिवेश के साथ ही अपनी मां इंदिरा शर्मा के सहयोग को अप्रतिम मानती हैं। कारण यह कि वे मालवी में ही बतियाती और कथा-भजन आदि भी मालवी में ही सुनाती हैं। मां से वे

मालवी शब्दों के हिंदी अर्थ समझती रहीं जिससे यह शब्दकोश तैयार करने में आसानी हो गई। भोली बेन की इच्छा थी कि यह शब्दकोश भाषा बोली अकादमी या मप्र साहित्य अकादमी से प्रकाशित हो जाए किंतु उनसे काफी पहले लोक भाषा मालवी का सबसे प्रमुख और प्रामाणिक 'मालवी-हिंदी शब्दकोश' उज्जैन के डॉ भगवतीलाल पुरोहित और डॉ प्रह्लाद चंद्र जोशी द्वारा लिखा और भाषा बोली अकादमी निदेशक बसंत निरगुणे द्वारा प्रकाशित किया जा चुका था, डॉ विकास दवे ने उन्हीं को यह दायित्व सौंपा कि डॉ पुरोहित वाले शब्दकोश से अपने शब्दकोश

का मिलान कर लें कि बेहतर अधिक बेहतर कौनसा है। अकादमी द्वारा असमर्थता व्यक्त करने पर अंतत: भोली बेन ने अपने दम पर इसके प्रकाशन का निर्णय ले लिया, कोराना काल से इस दिशा में काम शुरु कर दिया था जो अब प्रकाशित हुआ है।

मालवी बोली के लिये भोली बेन की सक्रियता

मालवी शब्दकोश के साथ ही व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की रचना 'तट की खोज' का 'किनारा की खोज' का मालवी अनुवाद कर चुकी है। जिसका अखंड संडे में मुकेश इंदौरी सहित अन्य साहित्यकार विमोचन कर चुके हैं। लघु कथाकार योगेंद्र नाथ शुक्ल की रचनाओं का मालवी में अनुवाद कर चुकी हैं। मालवी साहित्य की गद्य और पद्य में जो मिठास है उन साहित्यकारों की रचनाओं का भी अनुवाद कर चुकी हैं।संजा पर्व के गीतों की रंगीन किताब के साथ ही 'मालवी डब्ल्यो' नाम से उनकी कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हो चुका है।मालवी सुविचार आधारित उनकी किताब का लंदन में भी विमोचन हो चुका है। 'आज को ज्ञान' नामक पुस्तक इंडिया बुक रेकार्ड में दर्ज है। 'मालवी माण्डना' स्तंभ की लेखिका भोली बेन कहती हैं इंस्टाग्राम पर मालवी के जोक्स तो खूब चल रहे हैं, मैंने इससे ध्यान हटाने के लिए सोशल मीडिया पर मालवी के रस-छंद का अभियान भी चला रखा है।हिंदी की रचनाओं का मालवी में अनुवाद को लेकर उनका यह प्रयास रहता है कि यह लोकभाषा कॉलेजों के छात्रों के ज्ञान में तो सहयोगी बने ही साथ ही एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी मददगार साबित हो सके।

टेसू के फूलों से सजे पलाश, प्रकृति की छटा बनी आकर्षण का केंद्र

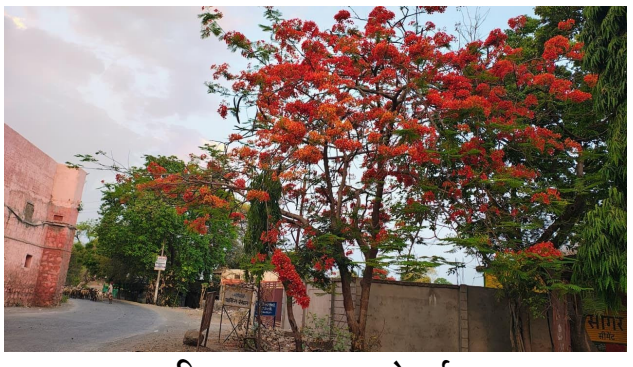

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

इंदौर। जिले के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों पलाश के पेड़ों पर खिले टेसू के फूल लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देपालपुर क्षेत्र के बनेडिया सहित आसपास के गांवों में लाल-नारंगी फूलों से लदे पलाश के वृक्ष प्रकृति की अनुपम छटा बिखेर रहे हैं। सड़कों के किनारे और खेतों में खिले इन फूलों को देखने के लिए राहगीर भी कुछ पल ठहरने को मजबूर हो रहे हैं। पतझड़ के मौसम में जहां अधिकांश पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वहीं पलाश के वृक्ष पत्तों के बिना टेसू के फूलों से पूरी तरह ढंक जाते हैं। लाल-लाल फूलों से सजा पूरा वृक्ष दूर से ही आकर्षित करता है और वातावरण में रंगीनता घोल देता है। देपालपुर-बनेडिया मुख्य मार्ग सहित क्षेत्र की अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे खिले पलाश के फूल मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पलाश पर टेसू के फूलों का खिलना होली पर्व के आगमन का संकेत माना जाता है। वरिष्ठजनों ने बताया कि पहले इन फूलों से प्राकृतिक रंग तैयार कर होली खेली जाती थी। प्राकृतिक रंग स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते थे, लेकिन समय के साथ बाजार में रासायनिक रंगों के प्रचलन के कारण यह परंपरा लगभग समाप्त हो गई है। अब अधिकांश लोग सूखे गुलाल से होली मनाते हैं।

30 साल पुराने भूमि सौदे पर विवाद गहराया, किसान ने लगाई जान-माल की सुरक्षा की गुहार

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर/बेटमा। लगभग तीन दशक पुराने भूमि सौदे को लेकर देपालपुर क्षेत्र में विवाद गहरा गया है। ग्राम दतोदा निवासी एक किसान ने बेटमा थाने में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि वर्ष 1996 में खरीदी गई कृषि भूमि का विक्रय पंजीयन आज तक नहीं कराया गया है। अब जमीन के बढ़े दामों के बीच विक्रेता पक्ष अतिरिक्त राशि की मांग कर रहा है तथा कब्जे से बेदखल करने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश चौधरी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उन्होंने सर्वे क्रमांक 145/2 की कृषि भूमि का सौदा वर्ष 1996 में तत्कालीन भूमि स्वामी से करीब 3.80 लाख रुपए में किया था। आरोप है कि पूरी राशि प्राप्त करने के बाद विक्रेता ने भूमि का कब्जा सौंप दिया था और यह आश्वासन दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर विक्रय पंजीयन भी करा दिया जाएगा। इसके बाद से वह लगातार भूमि का उपयोग और खेती-किसानी करते आ रहे हैं।

अतिरिक्त राशि मांगने का आरोप

आवेदन के अनुसार, वर्षों तक विक्रय पंजीयन कराने का आश्वासन दिए जाने के बाद जब हाल ही में पंजीयन कराने की बात उठाई गई तो विक्रेता पक्ष ने कथित रूप से अतिरिक्त धनराशि की मांग शुरू कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि साफ तौर पर कहा गया कि जब तक और पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक रजिस्ट्री नहीं कराई जाएगी तथा भूमि पर अधिकार भी नहीं रहने दिया जाएगा।

हथियारों के साथ पहुंचने का दावा

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 5 जून 2026 को ग्राम रामबड़ोदिया में 10 से 15 वाहनों में सवार होकर 100 से 150 लोग पहुंचे। शिकायतकर्ता का दावा है कि कुछ लोगों के पास बंदूक और तलवार जैसे हथियार भी थे। आरोप है कि इस दौरान उन्हें जमीन छोड़ने के लिए धमकाया गया और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई।

बेदखली की आशंका, पुलिस से कार्रवाई की मांग

किसान ने आवेदन में आशंका जताई है कि जमीन के वर्तमान बाजार मूल्य में हुई वृद्धि के कारण विक्रेता पक्ष सौदे से पीछे हटने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई करने, कब्जे में हस्तक्षेप रोकने तथा स्वयं और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है।

कई अधिकारियों को भेजी प्रतिलिपि

शिकायत की प्रतिलिपि गृह विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, कलेक्टर इंदौर तथा एसडीओपी देपालपुर को भी भेजी गई है। शिकायतकर्ता ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित आरोपितों की होगी।

पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगी स्थिति

मामला फिलहाल शिकायत के स्तर पर है। आवेदन में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस द्वारा जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम और आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

हाईपॉवर कमेटी पहुंची : भोपाल के निर्देश पर आए तीन सदस्यीय दल ने किया परीक्षण

बेजुबान श्यामू किस से कहे कि उसके जोड़ों में रहता है भीषण दर्द

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

उज्जैन, कीर्ति राणा। परिंदों को प्यास लगने पर तो वह छत या बालकनी में रखा खाली सकोरा गिरा कर या लगातार चीं चीं कर हमारा ध्यान आकर्षित करा देता है तो हम दाना-पानी का इंतजाम कर सकते हैं लेकिन किसी भी जानवर को अंदरुनी परेशानी हो तो वह अपनी पीड़ा किससे और कैसे कहे।जोड़ों के भीषण दर्द की परेशानी से श्यामू हाथी भी जूझ रहा है। महाकाल की सवारी का प्रमुख आकर्षण श्यामू को अपना पेट पालने के साथ ही महावत गोस्वामी परिवार के लिए भी रोटी की चिंता का भार है इसलिये उसे हर रोज 10-12 घंटे सड़कों पर भटकना ही पड़ता है। हाथ फैलाए किसी भिखारी को कुछ देने का मन भले ही ना करे किंतु गणेश जी के अवतार हाथी के दर्शन मात्र से ही मन में श्रद्धा का सागर हिलोरे मारने लगता है। श्रद्धालु आसपास नजर दौड़ाते हैं, केले, गुड़ की भेली, सांटा आदि जो भी मिल जाए हाथी बाबा को अर्पित करने के साथ ही उसे लेकर चलने वाले महावत को भी कुछ ना कुछ राशि भेंट करते ही हैं। किसी परिवार का एकमात्र जवान युवक जैसे परिवार के पालनहार का दायित्व निभाता है वही दायित्व 28 वर्षीय श्यामू पर भी है। उसे अपने साथ परिवार का भी पेट पालना है। श्यामू से पहले यह जिम्मेदारी रामू की थी। महावत श्रवण गोस्वामी का कहना है 1980 से 2016 तक रामू हाथी महाकाल की सवारी की शान रहता था। उसके दिवंगत होने के बाद से श्यामू हमारा सहारा है। 2006 से श्यामू को पाला है।2016 से 2025 तक वह हर सवारी में अनुशासित रहते काम कर रहा है। घर की जिम्मेदारी उठाने वाला मुखिया जैसे अपना दर्द-बीमारी को भुलाकर परिवार की रोजी-रोटी की चिंता में

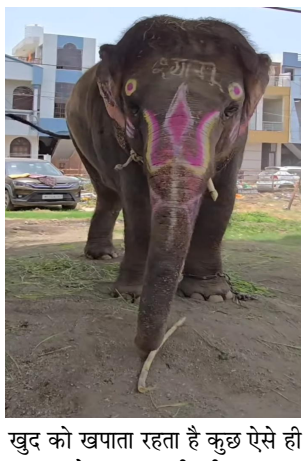

खुद को खपाता रहता है कुछ ऐसे ही हालात से श्यामू हाथी भी जूझ रहा है। महावत परिवार उसकी बीमारी को जानता तो है लेकिन वो सब जानते हैं कि श्यामू के प्रति श्रद्धालुओं के दया भाव से ही उनके घर का चूल्हा जल रहा है। श्यामू की बीमारी संबंधी जानकारी भोपाल पहुंच चुकी है। वन विभाग की चीफ वाइल्ड वार्डन डॉ संगीता राजोरा ने उसके स्वास्थ्य की बेहतरी के साथ बीमारी की विस्तृत रिपोर्ट के लिए तीन सदस्यीय हाईपॉवर कमेटी को उज्जैन भेजा है। इस समिति में पन्ना टाइगर रिजर्व से डॉ संजीव गुप्ता, उज्जैन के वेटरनरी डॉक्टर (पशु चिकित्सक) मुकेश जैन, इंदौर नगर निगम के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर जू) के प्रभारी अधिकारी/निदेशक डॉ. उत्तम यादव को श्यामू की जांच पड़ताल और हेल्थ अपडेट रिपोर्ट देने के लिये उज्जैन भेजा है। दो दिन पहले भी डॉ मुकेश जैन और वन विभाग का अमला श्यामू के परीक्षण के लिये पहुंचा था लेकिन गोस्वामी परिवार के भारी विरोध के चलते इस टीम को लौटना पड़ा था। महावत परिवार का आरोप था कि टीम के अधिकारी श्यामू को बलात अपने साथ ले जाने आए हैं। आज पहुंची इस हाईपॉवर कमेटी की समझाइश के बाद महावत परिवार श्यामू के इलाज में सहयोग के लिये राजी हुआ है। श्यामू गुजर रहा है इन दिक्कतों से इस त्रिसदस्यीय टीम के सदस्य डॉ उत्तम यादव ने चर्चा में कहा श्यामू जिस परेशानी से गुजर रहा है ऐसे

डॉ उत्तम यादव

में उसके लिये टोटल रेस्ट ही अधिक जरूरी है। हम महावत परिवार की परेशानी, धार्मिक मान्यताओं के विरोधी नहीं है लेकिन जीव दया की बात भी तो हमारे ग्रंथ कहते हैं। श्यामू के परीक्षण के पश्चात मिले लक्षणों से उसे जोड़ो में भीषण दर्द (जॉइंट डीजेनेरेटिव डिजीज) की शिकायत है।

क्यों होती है जॉइंट डीजेनेरेटिव डिजीज

हाथियों में होने वाली यह गंभीर और काफी आम समस्या है, विशेषकर वृद्ध, कैद में रहने वाले या अधिक वजन वाले हाथी इसके शिकार होते हैं। इस रोग में जोड़ों की उपास्थि धीरे-धीरे घिसने लगती है। परिणामस्वरूप जोड़ों में दर्द, सूजन और चलने-फिरने में कठिनाई होने लगती है। यह मनुष्यों के ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा ही रोग है।

श्यामू में बीमारी के ये लक्षण मिले

तीन सदस्यीय दल ने श्यामू के स्वास्थ्य की जांच के लिए मल-मूत्र के सैंपल के साथ अन्य परीक्षण भी किये हैं। जांच में पाया कि 28 वर्षीय श्यामू का वजन 3-4 हजार किलो (ओवर वेट) होने फेट बढ़ते जाने, हर दिन दस घंटे चलने से सारा भार पैरों पर पड़ने से वह लंगड़ाकर चल रहा है। पिछले पैर सतत बैंड होते जाने से आपस में टकरा रहे हैं। उसकी गर्दन पर फंगल इंफेक्शन बढ़ता जा रहा है। उसे उठने-बैठने में कठिनाई होने के साथ ही चलने की गति कम हो गई है, जोड़ों में सूजन के साथ ही सामान्य हाथियों जैसी गतिविधि कम होने के साथ ही भोजन में रुचि कम हो रही है। श्यामू पिछले 9 वर्षों से बाबा महाकाल की शाही सवारी में भगवान मनमहेश की प्रतिमा को अपनी पीठ पर लेकर नगर भ्रमण कराता है। उसका जन्म 8 नवंबर 1997 को असम के गोलाघाट में हुआ था। वर्ष 2000 में संत श्रवण गिरी महाराज उसे उज्जैन लेकर आए थे। वर्ष 2016 में रामू हाथी के बाद से श्यामू महाकाल की शाही सवारी की जिम्मेदारी निभा रहा है।

श्यामू को जितना आराम मिलेगा, उतनी ही जल्दी तबीयत में सुधार होगा : डॉ उत्तम यादव

डॉ. उत्तम यादव इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय (इंदौर जू) के प्रभारी अधिकारी/निदेशक हैं। वह लंबे समय से इस पद पर कार्यरत हैं और जू प्रबंधन के साथ-साथ वन्यजीवों के इलाज, ब्रीडिंग (प्रजनन), और बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉ उत्तम यादव ने इस प्रतिनिधि से चर्चा में बताया एशिया में पाए जाने वाले हाथी मकरा प्रजाति के होते हैं। श्यामू भी इसी प्रजाति का है। इस प्रजाति के हाथियों की औसत उम्र अधिकतम 70 वर्ष होती है जबकि अफ्रीकन प्रजाति के हाथियों की उम्र 90 वर्ष होती है। श्यामू की बीमारी के जो लक्षण हैं उसे देखते हुए दवाइयां तो अपनी जगह काम करेगी लेकिन बेहतर उपचार यही है कि कुछ महीने उसे टोटल रेस्ट मिले। चलने-फिरने से जितनी राहत मिलेगी, उतनी तेजी से वह ठीक होगा।

रंगवासा शराब दुकान पर लगाए जा रहे आरोपों को प्रबंधन ने बताया निराधार, नियमों के पालन का किया दावा

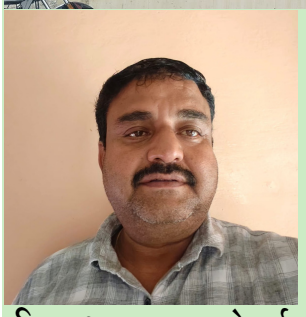

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। पिछले कुछ समय से रंगवासा स्थित लाइसेंसी शराब दुकान विभिन्न चर्चाओं और आरोप-प्रत्यारोपों के कारण सुर्खियों में बनी हुई है। इस बीच दुकान प्रबंधन ने सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया है कि दुकान का संचालन शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं आबकारी विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप किया जा रहा है तथा कुछ लोगों द्वारा तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर दुकान की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान के प्रबंधक जगदीश गेहलोत ने बताया कि रंगवासा शराब दुकान का संचालन पूरी पारदर्शिता एवं वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दुकान पर आने वाले ग्राहकों के लिए निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसके बावजूद कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा अन्य कारणों से मीडिया माध्यमों का उपयोग कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा आसपास के क्षेत्रों अथवा अन्य स्थानों पर ली गई तस्वीरों और घटनाओं को रंगवासा शराब दुकान से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि उनका दुकान से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऐसे प्रयासों से न केवल व्यवसाय की प्रतिष्ठा प्रभावित होती है बल्कि आम लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है।

लाइसेंसी संतोष मालवीय की कार्यप्रणाली की सराहना

स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि लाइसेंसी संतोष मालवीय द्वारा दुकान संचालन में अनुशासन, पारदर्शिता और विभागीय नियमों के पालन को प्राथमिकता दी जाती है। दुकान पर शासन के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थाएं बनाए रखने तथा वैधानिक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के प्रयासों को कई लोगों ने सकारात्मक पहल बताया है। सूत्रों के अनुसार दुकान प्रबंधन समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के संपर्क में रहकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त करता है और उनके अनुरूप व्यवस्थाओं को अद्यतन करता रहता है। इसी कारण दुकान संचालन को लेकर विभागीय मानकों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

आबकारी विभाग की सतत निगरानी

जानकारों का कहना है कि देपालपुर वृत्त में आबकारी विभाग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। विभागीय अमला समय-समय पर निरीक्षण एवं जांच की प्रक्रिया के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि लाइसेंसी दुकानों का संचालन नियमानुसार हो।

केसीसी रिश्वतकांड में नया मोड़: किसान का खाता ओवरड्यू तो फिर ऋण नवीनीकरण की प्रक्रिया कैसे बढ़ी? शाखा प्रबंधक की भूमिका पर उठे सवाल

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

गौतमपुरा। सेवा सहकारी संस्था मर्यादित अत्याना में केसीसी ऋण नवीनीकरण के नाम पर 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए दो कर्मचारियों के लोकायुक्त के हत्थे चढ़ने के बाद अब पूरे मामले में नए सवाल खड़े हो गए हैं। सहकारी संस्था के प्रभारी प्रबंधक अमन जोशी और सहायक समिति प्रबंधक रमेशचंद्र पंड्या की गिरफ्तारी के बाद जांच का दायरा बढ़ाने की मांग उठने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि शिकायतकर्ता किसान जाकिर हुसैन पटेल का खाता वास्तव में ओवरड्यू था और जमा राशि की रसीद तक नहीं कटी थी, तो फिर ऋण नवीनीकरण की प्रक्रिया किस आधार पर आगे बढ़ रही थी? लोकायुक्त की कार्रवाई ने जहां सहकारी संस्था के दो कर्मचारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं गौतमपुरा को-ऑपरेटिव बैंक की कार्यप्रणाली और शाखा प्रबंधन की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में आ गई है। ग्रामीणों और सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों का कहना है कि

इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच केवल रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह भी देखा जाना चाहिए कि ऋण प्रकरण किस स्तर तक पहुंचा और उसमें बैंक की क्या भूमिका रही।

शाखा प्रबंधक के बयान से बढ़ा विवाद

गौतमपुरा को-ऑपरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक राजेश चौधरी का कहना है कि किसान जाकिर हुसैन पटेल की जमा रसीद नहीं कटी है, इसलिए उसका खाता आज भी ओवरड्यू माना जा रहा है। दूसरी ओर किसान का दावा है कि उसने संबंधित राशि जमा कर दी थी तथा विड्रॉल स्लिप और बैंक पासबुक गुम होने की जानकारी भी बैंक प्रबंधन को दी गई थी। यहीं से कई महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े हो रहे हैं। यदि बैंक के रिकॉर्ड में किसान का खाता ओवरड्यू था, तो ऋण नवीनीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा क्यों हो रही थी? यदि खाता नियमित नहीं था तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा नवीनीकरण के नाम पर रिश्वत मांगने का आधार क्या था? और यदि किसान ने राशि जमा कर दी थी तो उसकी रसीद क्यों नहीं कटी? इन सवालों के स्पष्ट उत्तर अभी तक सामने नहीं आए हैं।

सबसे बड़ा सवाल: ओवरड्यू खाते पर प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ी?

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बैंक प्रबंधन स्वयं किसान के खाते को ओवरड्यू बता रहा है। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रक्रिया के अनुसार नया ऋण अथवा नवीनीकरण संभव नहीं माना जाता। ऐसे में यह जांच का विषय बन गया है कि क्या बैंक और संस्था के स्तर पर रिकॉर्ड में कोई विसंगति थी या फिर प्रक्रिया को जानबूझकर लंबित रखकर अवैध वसूली का दबाव बनाया जा रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि यदि कोई किसान वास्तव में पात्र नहीं था तो उसे स्पष्ट रूप से लिखित सूचना दी जानी चाहिए थी। वहीं यदि पात्र था तो उससे रिश्वत मांगना गंभीर भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।

दो कर्मचारी निलंबित, लेकिन क्या यहीं खत्म होगी जांच?

लोकायुक्त ट्रैप के बाद बहुउद्देश्यीय कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित (बी-पैक्स) अत्याना के प्रशासक एवं अंकेक्षण अध्यक्ष के.के. जमरे ने प्रभारी प्रबंधक अमन जोशी और सहायक समिति प्रबंधक रमेशचंद्र पंड्या को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय गौतमपुरा निर्धारित कर दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह चर्चा तेज है कि क्या कार्रवाई केवल दो कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे ऋण प्रकरण की प्रशासनिक और वित्तीय जांच भी कराई जाएगी। सहकारिता क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि किसी भी ऋण नवीनीकरण प्रक्रिया में कई स्तरों पर दस्तावेजों और रिकॉर्ड का परीक्षण होता है, इसलिए मामले के प्रत्येक चरण की जांच आवश्यक है।

एमडी बोले- सोमवार को होगी समीक्षा

इंदौर को-ऑपरेटिव विभाग के प्रबंध संचालक (एमडी) आलोक जैन ने कहा है कि शनिवार और रविवार अवकाश होने के कारण वे सोमवार को पूरे मामले की जानकारी लेकर ही कोई अधिकृत प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जांच में शाखा प्रबंधक या किसी अन्य अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एमडी के इस बयान के बाद अब निगाहें विभागीय जांच पर टिक गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि जांच में यह स्पष्ट होगा कि किसान के खाते की वास्तविक स्थिति क्या थी, जमा राशि का रिकॉर्ड क्यों विवादित है और ऋण नवीनीकरण प्रक्रिया में किस-किस स्तर पर जिम्मेदारी तय होती है।

संदीपनी विद्यालय में प्रभार को लेकर विवाद गहराया, वरिष्ठता की अनदेखी के आरोप

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

देपालपुर। शासकीय संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देपालपुर में प्रभारी प्राचार्य के पद को लेकर लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। विद्यालय के शिक्षकों द्वारा वरिष्ठता के आधार पर प्रभार दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। आरोप है कि वरिष्ठ शिक्षिका होने के बावजूद अरुणा सिंह को विद्यालय का प्रभार नहीं सौंपा गया, जबकि उनसे कनिष्ठ शिक्षिका अमिता मुंदड़ा के पास वर्तमान में विद्यालय संचालन की जिम्मेदारी है। जानकारी के अनुसार अरुणा सिंह की विभागीय जॉइनिंग अमिता मुंदड़ा से तीन दिन पूर्व की बताई जा रही है। ऐसे में विद्यालय के कई शिक्षकों का मानना है कि वरिष्ठता के सिद्धांत के अनुसार प्रभार अरुणा सिंह को मिलना चाहिए था। इस संबंध में शिक्षकों द्वारा संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आया है। विद्यालय के कुछ शिक्षकों का आरोप है कि पिछले लगभग एक वर्ष से यह मामला विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर लंबित है, जिससे विद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। शिक्षकों का कहना है कि उनकी ओर से कई बार वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पक्ष

रखा गया, किंतु अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

दूसरे विद्यालय का उदाहरण देकर उठाए सवाल

शिक्षक स्टाफ का कहना है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, देपालपुर में भी इसी प्रकार की स्थिति निर्मित हुई थी। वहां प्रभारी का दायित्व एक शिक्षक के पास था, लेकिन वरिष्ठता के आधार पर बाद में वरिष्ठ शिक्षिका को प्रभार सौंपा गया। ऐसे में संदीपनी विद्यालय के मामले में अलग व्यवस्था अपनाए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

शिक्षकों में असंतोष, दबाव के आरोप

कुछ शिक्षकों ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर आरोप लगाया कि जो शिक्षक वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि ऐसे शिक्षकों को अतिरिक्त कार्य सौंपे जा रहे हैं तथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा मामला

सूत्रों के अनुसार विद्यालय में प्रभार संबंधी विवाद की जानकारी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंच चुकी है। इसके बावजूद अब तक मामले का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।

कलेक्टर और संभागायुक्त से हस्तक्षेप की मांग

विद्यालय के शिक्षकों ने संकेत दिए हैं कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा एवं संभागायुक्त डॉ. सुदामा खाड़े से मुलाकात कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा वरिष्ठता नियमों के अनुरूप निर्णय की मांग करेंगे।

जांच से स्पष्ट हो सकती है स्थिति

शिक्षा विभाग से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि वरिष्ठता, विभागीय आदेशों तथा प्रभार संबंधी नियमों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकती है। वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय के शिक्षकों द्वारा उठाए जा रहे प्रश्नों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, ताकि शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित न हो और शिक्षकों में व्याप्त असंतोष समाप्त हो सके।

इनका कहना है

'प्रभार एवं वरिष्ठता से संबंधित मामलों के निराकरण की प्रक्रिया विभागीय स्तर पर जारी है। वर्तमान में स्थानांतरण नीति के तहत बड़ी संख्या में माध्यमिक शिक्षकों के आदेश भी जारी किए जाने हैं, जिसके कारण कुछ प्रकरणों के निस्तारण में समय लग रहा है। आगामी 8 से 10 दिनों में सभी लंबित मामलों का परीक्षण कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं, बल्कि शासन के प्रचलित नियमों एवं विभागीय प्रावधानों के अनुसार ही निर्णय किया जाता है। वरिष्ठता का निर्धारण भी निर्धारित शासकीय नियमों और सेवा अभिलेखों के आधार पर किया जाता है। जो अधिकारी अथवा कर्मचारी नियमों के अनुसार वरिष्ठता की श्रेणी में आएगा, उसे ही प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।

– शांता स्वामी भार्गव, जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), इंदौर

मानसून से पहले टिटहरी के संकेतों पर टिकी किसानों की नजर

अंडे देने के स्थान और व्यवहार से वर्षा का अनुमान लगाते हैं ग्रामीण, पीढ़ियों से चली आ रही है परंपरा

विश्वनाथ समाचार न्यूज नेटवर्क

इन्दौर। मानसून की दस्तक से पहले जहां मौसम विभाग अत्याधुनिक तकनीक, उपग्रहों और वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर वर्षा का पूर्वानुमान जारी करता है, वहीं ग्रामीण अंचलों में आज भी प्रकृति के संकेतों को मौसम की सटीक जानकारी का माध्यम माना जाता है। गांवों में रहने वाले किसान और बुजुर्ग वर्षों से जीव-जंतुओं और पक्षियों के व्यवहार का अवलोकन कर मौसम का अनुमान लगाते आए हैं। उनका मानना है कि प्रकृति में होने वाली छोटी-छोटी गतिविधियां आने वाले मौसम की सूचना पहले ही दे देती हैं। ग्रामीणों के अनुसार चींटियों का अंडे लेकर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना, चिड़ियों का धूल में बार-बार नहाना, मेंढकों की आवाज बढ़ना तथा वर्षाकाल में दिखाई देने वाले कीट-पतंगों की सक्रियता वर्षा के संकेत माने जाते हैं। इन्हीं प्राकृतिक संकेतों में टिटहरी पक्षी का विशेष महत्व है। ग्रामीण समाज में टिटहरी को प्रकृति का जीवंत मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसके व्यवहार और अंडों की स्थिति के आधार पर वर्षा का अनुमान लगाया जाता है।

अंडों की संख्या और स्थान से लगाते हैं वर्षा का अनुमान

इलाके के बुजुर्गों का कहना है कि टिटहरी के अंडे देने का स्थान और उसकी संख्या को वर्षा से जोड़कर देखा जाता है। परंपरागत मान्यता के अनुसार यदि टिटहरी चार अंडे देती है तो इसे अच्छी और भरपूर वर्षा का संकेत माना जाता है। वहीं यदि वह अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर अंडे देती है तो ग्रामीण इसे अधिक बारिश होने की संभावना से जोड़ते हैं। इसके विपरीत यदि टिटहरी गड्ढों या निचले स्थानों पर अंडे दे तो कम वर्षा होने की आशंका व्यक्त की जाती है।

जहां टिटहरी अंडे दे, वह भूमि मानी जाती है उपजाऊ

बनेडिया गांव के वरिष्ठ किसान लालजीराम पटेल ने बताया कि आज भी कई किसान टिटहरी के व्यवहार का बारीकी से अध्ययन करते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण परंपराओं में टिटहरी द्वारा चुने गए स्थान को विशेष महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जिस खेत में टिटहरी अंडे देती है, वहां की भूमि उपजाऊ होती है और ऐसे खेतों में अच्छी पैदावार की संभावना रहती है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक, संदीप परमार द्वारा 106, लीला रेसीडेंसी, कॉलोनी वार्ड नंबर 07, देपालपुर, जिला इंदौर म.प्र. से प्रकाशित तथा उदयरत्न ऑफसेट 170/2, दारू गोडाउन के आगे आगर रोड उज्जैन से मुद्रित।
मो.न.9755161156 सम्पादक संदीप परमार, प्रबंध संपादक जितेन्द्र चौहान, RNI No. MPHIN/25/A4357 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र देपालपुर रहेगा), (नोट: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी)